

वैश्विक बैंकिंग प्रणाली, बासेल III सुधारों के प्रगामी कार्यान्वयन और त्वरित नीतिगत उपायों के बल पर कोविड-19 के शुरुआती कुप्रभावों को सफलतापूर्वक सहन कर गयी। आगे के सुधारों का कार्यान्वयन एक वर्ष के लिए टाल दिया गया ताकि बैंकों और पर्यवेक्षकों की परिचालन क्षमता को बढ़ाया जा सके और वे इस महामारी से निपट सकें। भविष्य में, बैंक क्रेडिट में वृद्धि मंद रहने और लाभप्रदता का परिदृश्य धूमिल बने रहने के आसार हैं तथा बैंकों की आस्ति गुणवत्ता, पूंजी और चलनिधि की स्थिति खराब होने की आशंकाएं बनी हुई हैं।

1. भूमिका

II.1 आज जबकि कोविड-19 की भीषण मार से दुनिया कराह रही है और इसकी दूसरी लहर आर्थिक संवृद्धि, निवेश और व्यापार के सामने मुंह बाये खड़ी है तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था एक ऐसी कठिन चुनौती के दौर से गुजर रही है, जैसी हाल के इतिहास में कभी देखी नहीं गयी। इस महामारी को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भविष्यवाणी की है कि वर्ष 2020 के दौरान वैश्विक उत्पादन में तीव्र गिरावट आएगी (चार्ट II.1 ए)।¹ वैश्विक वित्तीय प्रणाली, जिसमें बैंक केंद्रीय भूमिका में थे, वर्ष 2019 के दौरान सुदृढ़ हो रही थी जिसके मूल में थे लगातार किए जा रहे विनियामकीय सुधार। नीतिगत उपायों का ही यह परिणाम था कि गैर-वित्तीय क्षेत्र को दिए गए बैंक ऋण में 2019 की दूसरी तिमाही से तेजी आने लगी (चार्ट II.1 बी और सी)। उच्च पूंजी बफर और बेहतर चलनिधि अनुपात के बल पर वैश्विक बैंकिंग प्रणाली ने कोविड-19 के शुरुआती झटकों को सफलतापूर्वक झेल लिया जिसमें त्वरित गति से उठाए गए अभूतपूर्व नीतिगत कदमों ने भी मदद की। हालांकि, कोविड-19 महामारी आने के साथ ही, बैंक ऋण वृद्धि वर्ष 2020 की प्रथम तिमाही में अचानक बाधित हो गयी, विशेष रूप से उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएम्ई) में। तथापि, इसकी प्रतिक्रियास्वरूप उठाए गए नीतिगत कदमों से वित्तीय हालात के तनाव को कम करने और दूसरी तिमाही में बैंक क्रेडिट-वृद्धि को बहाल करने में मदद मिली।

II.2 वर्ष 2021 का परिदृश्य अभी भी अनिश्चित बना हुआ है। हाउसहोल्ड्स, गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट्स और सरकारों (राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय) द्वारा भारी मात्रा में लिए गए कर्ज का बोझ गंभीर चिंता का विषय है। वैश्विक वित्तीय प्रणाली का भावी परिदृश्य बहुत कुछ इस बात पर निर्भर कर रहा है कि मानव स्वास्थ्य के लिए उत्पन्न यह संकट दूर कैसे होगा और समष्टि आर्थिक स्थितियों की बहाली की गति, उसका स्थायित्व और दायरा कैसा और कितना रहेगा। साथ ही, वैश्विक वित्तीय स्थिरता के सम्मुख जोखिम अपने उच्च स्तर पर बने हुए हैं।

II.3 शेष अध्याय को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है। भाग 2 में वैश्विक बैंकिंग नीतियों में हुए सुधारों की विकास-यात्रा और उनके कार्यान्वयन को चित्रित करने का एक प्रयास है। भाग 3 इस कठिन चुनौती की घड़ी में वैश्विक बैंकिंग प्रणाली के प्रदर्शन की समीक्षा करता है। विश्व के 100 सबसे बड़े बैंकों का एक संक्षिप्त पूर्वावलोकन भाग 4 में प्रस्तुत किया गया है। भाग 5 में इस अध्याय के निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

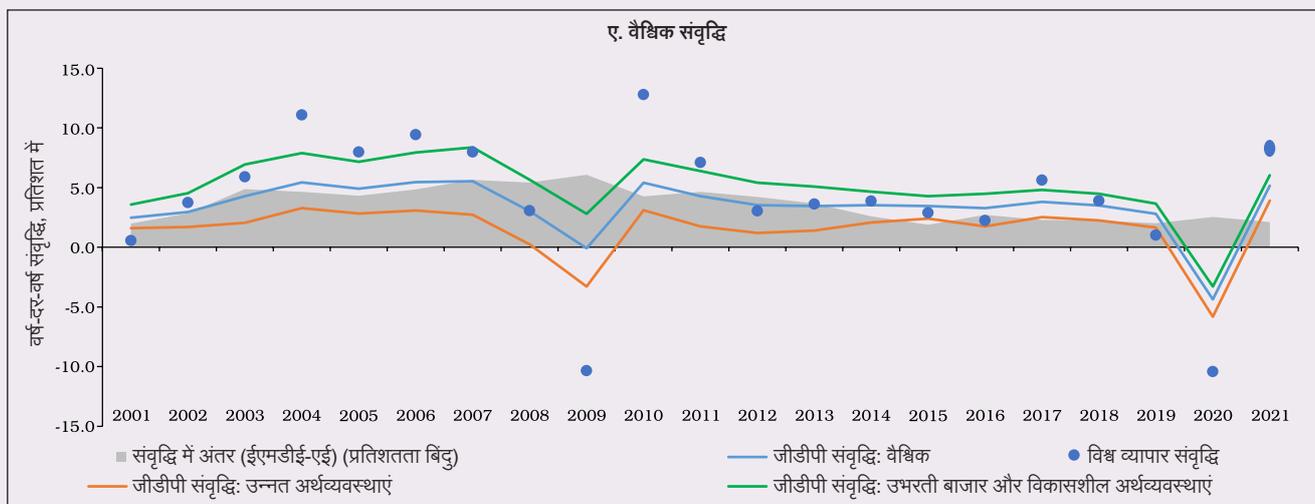
2. वैश्विक बैंकिंग नीतिगत गतिविधियाँ

II.4 बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) के सदस्य देशों ने बासेल III मानकों को लागू करने में 2019 के बाद से प्रगति की²। जैसा कि ऊपर भी उल्लेख किया गया है, बैंकों ने इस अवधि में पूंजी और चलनिधि बफर का निर्माण किया जबकि कर्ज पोषित आस्तियों में कमी लायी गयी। यद्यपि, वैश्विक

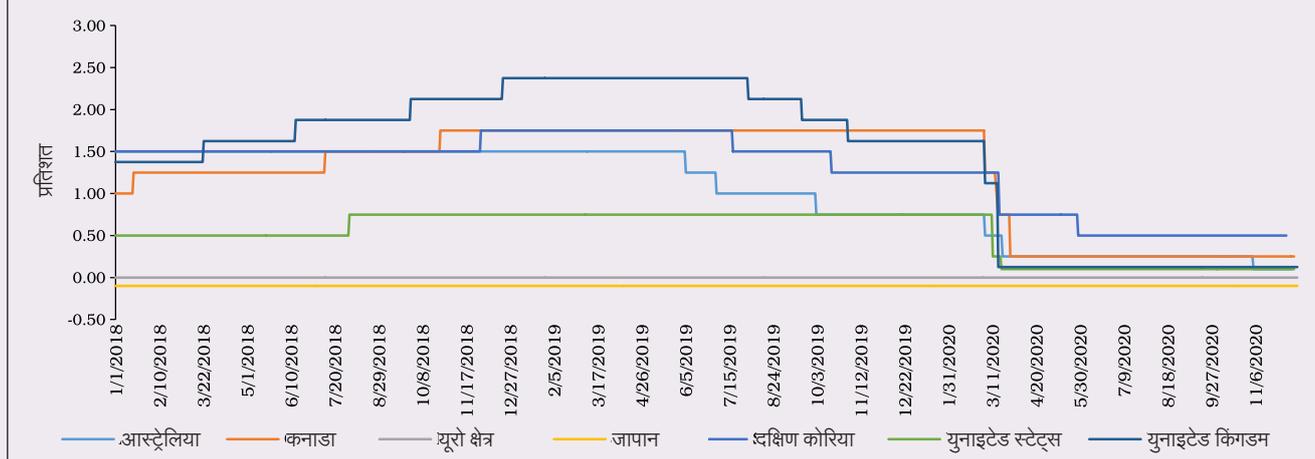
¹ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (2020), 'वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक – ए लॉग एण्ड डिफिकल्ट असेसमेंट', 7 अक्टूबर, <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020>. पर उपलब्ध है। अक्टूबर 2020 में डब्ल्यूओ में किए गए अपडेशन में जून 2020 के अपडेशन की तुलना में संकुचन की गंभीरता कम दिखी।

² बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (2020), बासेल मानकों का कार्यान्वयन: बासेल III विनियामक सुधारों के कार्यान्वयन पर जी 20 के अग्रणी देशों की रिपोर्ट, 3 नवंबर, <https://www.bis.org/bcbs/publ/d510.pdf> पर उपलब्ध है।

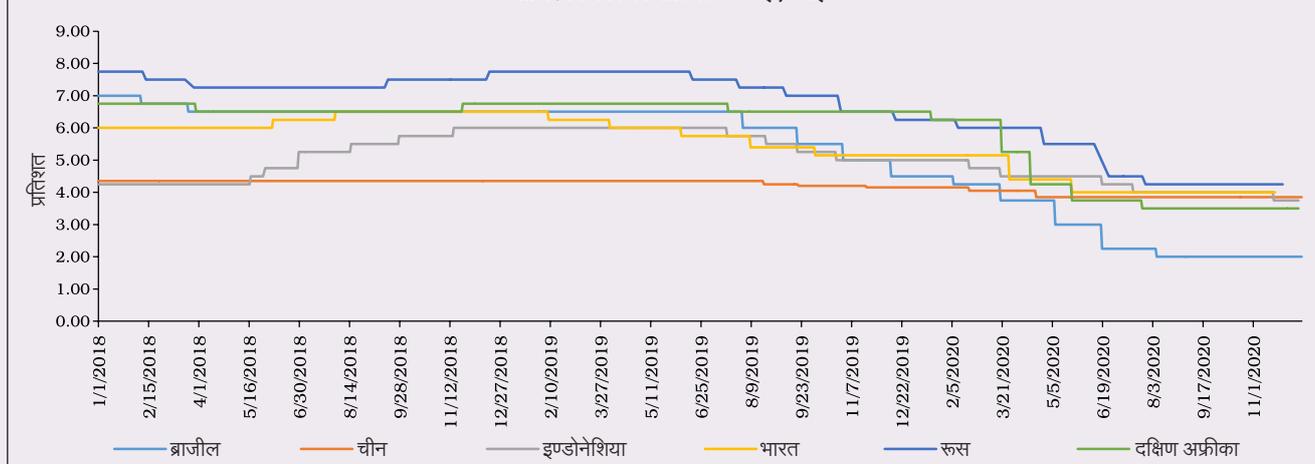
चार्ट II.1: समष्टि परिदृश्य



बी. केंद्रीय बैंकों की नीतिगत दरें – एई



सी. केंद्रीय बैंकों की नीतिगत दरें – ईएमडीई



टिप्पणी: 2020 और 2021 के आंकड़े आईएमएफ द्वारा व्यक्त पूर्वानुमान हैं।

स्रोत: आईएमएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेस, अक्टूबर 2020; बीआईएस नीतिगत दर सांख्यिकी, 19 नवंबर 2020।

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2019-20

महामारी से उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए, बासेल III मानकों (जिन्हें दिसंबर 2017 में अंतिम रूप दिया गया), संशोधित बाजार जोखिम ढांचे (जिसे जनवरी 2019 में अंतिम रूप दिया गया) और संशोधित पिलर 3 प्रकटन अपेक्षाओं (जिन्हें दिसंबर 2018 में अंतिम रूप दिया गया था) के क्रियान्वयन की तारीखें 01 वर्ष के लिए टालते हुए 01 जनवरी 2023 कर दी गयीं³। बावजूद इसके, इस बात की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि इस महामारी से बैंकों की पूंजी पर लगने वाले आघात के चिह्न बने रहेंगे।

II.5 वित्तीय क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए जो प्रमुख संस्थागत सुधार किए गए, उन्हीं के एक भाग के तौर पर वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) का गठन किया गया। इन सुधारों की चार प्रमुख बातें हैं: (i) वित्तीय संस्थानों को अधिक आघातसहनीय बनाना; (ii) इतने बड़े कि फेल न हो सकें (टीबीटीएफ) वाली घटना को समाप्त करना; (iii) व्युत्पन्नी बाजार को अधिक सुरक्षित बनाना; और (iv) सुदृढ़ गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता (एनबीएफआई) को बढ़ावा देना। कदाचार के जोखिम को कम करने के लिए अभिशासन के मानकों को मजबूत बनाने के लिए; प्रतिनिधि बैंकिंग में गिरावट से निपटने के लिए; वित्तीय स्थिरता की दृष्टि से फिनटेक के निहितार्थ का विश्लेषण करने के लिए; वित्तीय नवाचारों के लिए; भुगतान प्रणालियों के लिए; साइबर सुदृढ़ता के लिए; और बाजार विलगीकरण के लिए भी काम चल रहा है।

2.1 सुदृढ़ वित्तीय संस्थाओं का गठन

II.6 पूंजी, चलनिधि और प्रणालीगत महत्व रखने वाले वैश्विक बैंकों (जी-एसआईबी) के लिए बने बासेल फ्रेमवर्क⁴ के कार्यान्वयन में काफी प्रगति हुई है। बीआईएस के सभी 27 सदस्य देशों ने जोखिम-आधारित पूंजी, चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) विनियम, पूंजी संरक्षण बफर्स और

प्रतिचक्रीय पूंजी बफर्स (सीसीवाईबी) के लिए बने सभी अंतिम नियमों को लागू कर दिया है। जहाँ एक ओर सभी सदस्य देश जो कि जी-एसआईबी के अपने देश हैं, उन्होंने अपने जी-एसआईबी के लिए अंतिम नियम लागू कर दिए हैं, वहीं इनमें से छब्बीस ऐसे सदस्य देश हैं जिन्होंने प्रणालीगत महत्व रखने वाले अपने घरेलू बैंकों (डी-एसआईबी) पर ये नियम लागू किए हैं। सभी सदस्यों ने निवल स्थायी निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) के लिए अंतिम या मसौदा नियम जारी कर दिए हैं⁵। इसके अलावा, लीवरेज अनुपात, प्रतिपक्षी ऋण जोखिम को मापने के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण (एसए-सीसीआर), बड़े जोखिमों (एलईएक्स) के आकलन और उन्हें नियंत्रित करने हेतु पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क, अंतर-दिवस-चलनिधि प्रबंधन के लिए निगरानी उपायों, केंद्रीय रूप से समाशोधित न किए जाने वाले व्युत्पन्नियों (एनसीसीडी) के लिए मार्जिन अपेक्षाओं, संशोधित प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क, निधियों में इक्विटी निवेश के लिए पूंजी अपेक्षाओं और पिलर 3 की संशोधित प्रकटीकरण अपेक्षाओं के संबंध में भी अधिकांश सदस्य देश (22 से 26 के बीच) या तो अंतिम नियम लागू कर चुके हैं या नियमों का मसौदा प्रकाशित कर चुके हैं⁶।

2.2 व्युत्पन्नी बाजार को अधिक सुरक्षित बनाना

II.7 ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) व्युत्पन्नी बाजार-सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। सितंबर 2020 के अंत तक, ओटीसी व्युत्पन्नी लेनदेन के लिए समग्र व्यापार रिपोर्टिंग अपेक्षाओं और एनसीसीडी के लिए अंतरिम पूंजी अपेक्षाओं को एफएसबी के 23 देशों (कुल 24) में लागू कर दिया गया है, हालांकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें तो व्यापार रिपोर्टिंग को अभी पूरी तरह प्रभावी बनाया जाना शेष है। अनिवार्य केंद्रीय समाशोधन (17 देश), प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग (13 देश), केंद्रीकृत रूप से समाशोधित न किए जाने वाले व्युत्पन्नियों के लिए

³ वैश्विक बैंकिंग प्रणाली पर कोविड-19 के प्रभाव से उत्पन्न वित्तीय स्थिरता से जुड़ी प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए मार्च 2020 में, सेंट्रल बैंक गवर्नरों के समूह और पर्यवेक्षण प्रमुखों ने बैंकों और पर्यवेक्षकों की परिचालनगत क्षमता को और अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ उपायों पर मुहर लगायी।

⁴ बासेल फ्रेमवर्क बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) के मानकों का पूरा सेट है।

⁵ भारत में बैंकों के लिए एनएसएफआर पर अंतिम दिशानिर्देश मई 2018 में प्रकाशित किए गए थे। ये दिशानिर्देश जो 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी होने थे, उन्हें 1 अप्रैल 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

⁶ भारत में प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क को अपनाना अभी प्रारंभ नहीं हो सका है, जबकि गैर-केंद्रीय रूप से समाशोधित व्युत्पन्नियों (एनसीसीडी) के लिए मार्जिन आवश्यकता का कार्यान्वयन प्रगति पर है।

⁷ एफएसबी (2020), ओटीसी डेरिवेटिव्स मार्केट रिफॉर्मर्स: 2020 नोट ऑन इंप्लीमेंटेशन प्रोग्रेस, 25 नवंबर, <https://www.fsb.org/2020/11/otc-derivatives-market-reforms-2020-note-on-implementation-progress/> पर उपलब्ध है।

मार्जिन अपेक्षाओं (16 देश) और एनसीसीडी के लिए अंतिम पूंजी अपेक्षाओं (8 देश) से संबंधित फ्रेमवर्क का क्रियान्वयन जारी है।

2.3 सुदृढ़ गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता को प्रोत्साहित करना

II.8 वर्षों से, वैश्विक वित्तीय पटल पर गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थ वित्तपोषण के एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक स्रोत के रूप में अपनी उपस्थिति को और प्रभावी बनाते जा रहे हैं। वे बैंकों सहित वित्तपोषक संस्थाओं के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता क्षेत्र (एनबीएफआई)⁸ की कुल वित्तीय आस्तियाँ वर्ष 2019 में 8.9 प्रतिशत बढ़कर 200.2 ट्रिलियन यूएस डालर हो गयीं (जबकि पिछले वर्ष इनमें थोड़ी गिरावट दर्ज की गयी थी)। यह वृद्धि व्यापक स्तर पर हुई थी जिसका प्रमुख कारण यह था कि निवेश निधियों (जो मुख्य रूप से मूल्यन का प्रभाव दर्शाती हैं), पेंशन निधियों और बीमा निगमों में वृद्धि-दर अधिक रही थी⁹। वर्ष के दौरान, पूरे विश्व की कुल वित्तीय आस्थियों और बैंकों की वित्तीय आस्थियों में क्रमशः 6.6 प्रतिशत और 5.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

II.9 इस प्रकार 2019 में कुल वैश्विक वित्तीय मध्यस्थता में लगभग आधी हिस्सेदारी एनबीएफआई क्षेत्र की रही, जो कि वित्तीय प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों के साथ इस क्षेत्र की बढ़ती संबद्धता का परिचायक है और इसमें प्रणालीगत जोखिमों का खतरा भी निहित है।

II.10 गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थों के लिए नीतिगत सुधारों का कार्यान्वयन प्रगति पर है और यह वित्तीय प्रणाली को उदार और

सुदृढ़ बनाने में योगदान कर रहा है¹⁰। जहाँ मुद्रा बाजार निधियों (एमएमएफ) के लिए मूल्यन, चलनिधि प्रबंधन और स्थिर निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) से जुड़े अंतिम कार्यान्वयन उपायों को कुल 24 सदस्य देशों में से छह देशों द्वारा अभी लागू किया जाना शेष था, नौ देशों ने प्रोत्साहन संरक्षण व्यवस्था और प्रतिभूतीकरण संबंधी प्रकटीकरण अपेक्षाओं को लागू नहीं किया था। भारत में इन दोनों का कार्यान्वयन किया जा चुका है।

2.4 जलवायु संबंधी वित्तीय प्रकटीकरण

II.11 एफएसबी ने 2015 में जलवायु-संबंधी वित्तीय प्रकटीकरण (टीसीएफडी) पर कार्यदल का गठन किया था¹¹ और 2017 में इसने अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया। टीसीएफडी की सिफारिशों को अपनाने की स्थिति पर तीसरी रिपोर्ट (29 अक्टूबर, 2020) में इस बात के संकेत मिले कि जलवायु संबंधी वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण में लगातार वृद्धि हुई है। इसमें इस बात को भी रेखांकित किया गया कि अधिकाधिक सटीकता और तुलनीयता लाने के लिए यह आवश्यक है कि प्रकटीकरण के स्तर में लगातार सुधार किया जाए।

2.5 प्रतिनिधि बैंकिंग¹² और धन-प्रेषण

II.12 विश्व स्तर पर, प्रतिनिधि बैंकिंग में हाल के वर्षों में जोखिम-परहेज (डी-रिस्कंग) के कारण कमी आयी है। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली, प्रेषण और सीमा-पार भुगतान तक पहुंच पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। नवंबर 2015 से, एफएसबी ने प्रतिनिधि बैंकिंग संबंधों में गिरावट तथा धन-प्रेषण सेवा प्रदाताओं (आरएसपी) की बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच में

⁸ एनबीएफआई क्षेत्र में वे सभी वित्तीय संस्थाएं शामिल हैं जो केंद्रीय बैंक, बैंक या सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं नहीं हैं, इस प्रकार इनमें बीमा निगम, पेंशन फंड या वित्तीय सहायक कंपनियाँ शामिल हैं। अन्य वित्तीय मध्यस्थ (ओएफआई), जो एनबीएफआई क्षेत्र का ही एक उपसमुच्चय है, में सभी वित्तीय संस्थाएं शामिल हैं जो केंद्रीय बैंक, बैंक, सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं, बीमा निगम, पेंशन फंड या वित्तीय सहायक नहीं हैं।

⁹ एफएसबी एनबीएफआई गतिविधियों के आकार, संरचना और रुझानों की वार्षिक निगरानी करता है। वर्ष 2019 से संबंधित एनबीएफआई पर नवीनतम जानकारी 16 दिसंबर 2020 को प्रकाशित 'ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट ऑन नॉन-बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन 2020' से ली गयी है, जो <https://www.fsb.org/2020/12/global-monitoring-report-on-non-bank-financial-intermediation-2020/> पर उपलब्ध है।

¹⁰ वित्तीय स्थिरता बोर्ड (2020), 'इम्प्लीमेंटेशन एण्ड इफेक्ट्स ऑफ दि जी20 फाइनेंशियल रेगुलेटरी रिफॉर्म: एनुअल रिपोर्ट', 13 नवंबर, <https://www.fsb.org/2020/11/implementation-and-effects-of-the-g20-financial-regulatory-reforms-2020-annual-report/> पर उपलब्ध है।

¹¹ टीसीएफडी का उद्देश्य था- 'निवेशकों, ऋणदाताओं और बीमा हामीदारों को उनके जलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिमों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए कंपनियों द्वारा उपयोग किए जाने हेतु एक स्वैच्छिक, सुसंगत प्रकटीकरण सिफारिशों का सेट विकसित करना।'

¹² एफएसबी प्रतिनिधि बैंकिंग को एक बैंक ("संवाददाता बैंक") द्वारा किसी दूसरे बैंक ("प्रतिवादी बैंक") को बैंकिंग सेवाओं प्रदान करने वाली व्यवस्था के रूप में परिभाषित करता है।

आयी कमी को दूर करने के लिए कार्य-योजना बनायी है¹³। धन-प्रेषण सेवा प्रदाताओं (आरएसपी) की बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए एफएसबी द्वारा मार्च 2018 में कई उपायों की सिफारिश की और इसने आरएसपी को मिलने वाली बैंकिंग सेवाएं बंद हो जाने के पीछे निहित कारकों की पहचान की गयी जैसे कि कम लाभप्रदता, काला धन शोधन निरोध / आतंकवाद वित्तपोषण निरोध (एएमएल/सीएफटी) की दृष्टि से धन-प्रेषण क्षेत्र में कथित तौर पर मौजूद उच्च जोखिम विरोधी, आरएसपी का पर्यवेक्षण और उनसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुपालन की अपेक्षा।

II.13 इस स्थिति में सुधार लाने के विभिन्न उपायों के बावजूद, प्रतिनिधि बैंकिंग में 2019 के दौरान गिरावट जारी रही, हालांकि इसकी गति धीमी जरूर हुई। दुनिया भर में सक्रिय प्रतिनिधि बैंकों की संख्या 2019 के दौरान 3 प्रतिशत गिर गयी और 2011 और 2019 के बीच यह गिरावट 22 प्रतिशत तक रही¹⁴। इस सब के बावजूद, प्रतिनिधि बैंकिंग सीमा-पार भुगतान में अभी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

2.6 कदाचार जोखिम

II.14 एफएसबी ने नवंबर 2018 में कुछ उपाय लागू किए जिनका उपयोग करके पर्यवेक्षक और फर्म अपनी संस्थाओं के भीतर कदाचार की घटनाओं के लिए वरिष्ठ प्रबंधन की जवाबदेही बढ़ाते हुए वित्तीय संस्थानों के अभिशासन ढांचे को मजबूत बनाने में योगदान दे सकती हैं। इन सिफारिशों में मुआवजे की व्यवस्था के प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए कुछ महत्वपूर्ण डेटा-सेट को चिह्नित किया गया है। ये उपाय एफएसबी की कदाचार कार्य-योजना के अन्य तत्वों, जिसमें मुआवजे से जुड़ी सिफारिशें भी शामिल हैं, के पूरक बनते हैं जिससे जोखिम और प्रोत्साहन में बेहतर तालमेल स्थापित हो पाता है। अपने सदस्यों द्वारा किए गए सर्वेक्षण पर आधारित

एफएसबी की एक रिपोर्ट यह बताती है कि 'कदाचार विश्लेषण' और 'सूक्ष्म विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण' के लिए पर्यवेक्षी प्रौद्योगिकी (सुपटेक) का उपयोग हाल के वर्षों में बढ़ा है, जिसका मुख्य कारण है कि इन क्षेत्रों में मूल्यांकन की प्रकृति अपेक्षाकृत नियम-आधारित है। वहीं, पहले से प्रचलित पारंपरिक बाजार निगरानी तंत्रों के उपयोग में किंचित कमी आयी है। इसके अलावा, वित्तीय उत्पादों की गलत बिक्री का पता लगाने और ऐसे वित्तीय परामर्शदाताओं (सलाहकारों) की पहचान करने के लिए जिनके द्वारा कदाचार किए जाने का उच्च जोखिम होता है, पर्यवेक्षित यंत्र अधिगम (एमएल) उपकरणों के उपयोग में वृद्धि हुई है¹⁵।

2.7 कोविड-19 संकट पर केंद्रीय बैंकों की प्रतिक्रियाएँ

II.15 दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने इस महामारी के कुप्रभाव से राहत देने और हाउसहोल्ड्स तथा फर्मों के लिए ऋण की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनायी¹⁶। लाभांशों या शेयरों की पुनर्खरीद के माध्यम से किए जाने वाले लाभ-वितरण पर प्रतिबंध लगाते हुए अथवा सरकारी ऋण की गारंटी के माध्यम से या दोनों माध्यमों से पूंजी के स्तर को बढ़ाया गया। ऋण प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए, विनियामकों ने सरकारी गारंटी द्वारा कवर किए गए ऋणों के लिए जोखिम भार को माफ कर दिया और कुछ लक्षित उधारकर्ताओं, विशेष रूप से छोटी फर्मों में बैंकों के जोखिम के लिए जोखिम भारों को कम कर दिया। जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ने बड़े परिसंपत्ति खरीद कार्यक्रमों को सुविधाजनक बनाने और बैंकों को सरकारी बॉन्ड बाजारों में मध्यस्थता हेतु प्रोत्साहित करने के लिए बैंकों के लीवरेज जोखिम उपायों के अंतर्गत केंद्रीय बैंक आरक्षित निधि और सरकारी बॉन्ड होल्डिंग्स से छूट प्रदान कर दी। बहुत से देशों में, केंद्रीय बैंकों ने प्रतिचक्रिय पूंजी बफर्स को जारी करने

¹³ एफएसबी (2020), 'इनहासिंग क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट्स: जी20 को स्टेज 1 रिपोर्ट', 8 अप्रैल, <https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P090420-1.pdf> पर उपलब्ध।

¹⁴ बीआईएस (2020), 'न्यू करेस्पॉन्डेंट बैंकिंग डेटा – दि डिक्लाइन कंटीन्यूज एट अ स्लोअर पेस', 31 अगस्त, https://www.bis.org/cpmi/paysysinfo/corr_bank_data/corr_bank_data_commentary_2008.htm पर उपलब्ध है।

¹⁵ एफएसबी (2020), 'दि यूएस ऑफ सुपरवाइजरी एण्ड रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी बाई अथॉरिटीज एण्ड रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशंस', 9 अक्टूबर, <https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P091020.pdf> पर उपलब्ध।

¹⁶ आईएमएफ (2020), 'ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट', अक्टूबर, <https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2020/10/13/global-financial-stability-report-october-2020> पर उपलब्ध है।

की अनुमति बैंकों को दे दी। कुछ देशों में बैंकों से कहा गया कि वे पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी)¹⁷ का इस्तेमाल ऋण को बढ़ावा देने में करें और फिर जैसे-जैसे स्थिति में सुधार आएगा, धीरे-धीरे अपनी आय से बचत करते हुए उसका पुनः निर्माण करें। कई देशों ने महामारी से प्रभावित ऋणों के आस्ति वर्गीकरण की यथास्थिति बनाए रखने की अनुमति प्रदान की; इस आस्थगन के लिए प्रावधानीकरण अपेक्षित था, अतः इससे पूंजी का संरक्षण हुआ। बैंकों को बाध्य किया गया, चाहे विनियमन के जरिए या सख्त प्रशासनिक दिशानिर्देशों के जरिए, कि वे पूंजी के वितरण को रोके।

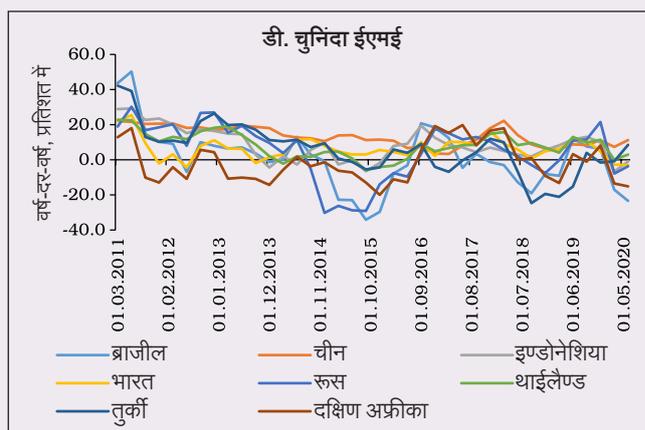
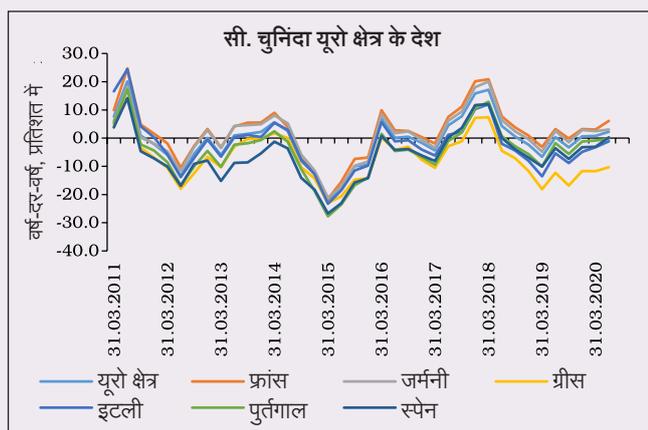
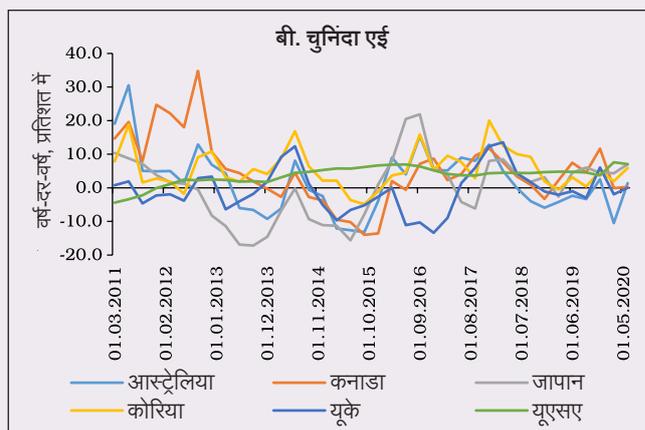
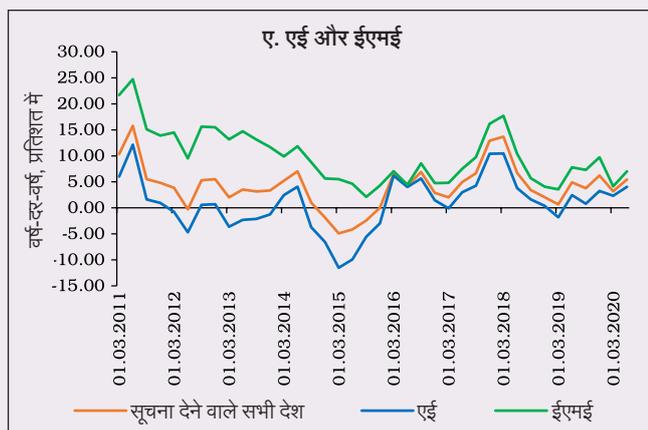
3. वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र का प्रदर्शन

II.16 पिछले दशक में 2019 तक उत्तरोत्तर विनियामकीय सुधारों को कार्यान्वित करते हुए, वैश्विक बैंकिंग प्रणाली ने अपने लिए एक मजबूत आधार तैयार कर लिया था, कि तभी वैश्विक महामारी की मार पड़ी और वास्तविक क्षेत्र में ऋण आपूर्ति ठप पड़ गयी।

3.1 बैंक क्रेडिट में वृद्धि¹⁸

II.17 पूरी दुनिया में एक साथ आयी मंदी के साथ ही, ज्यादातर एई और ईएमई में निजी गैर-वित्तीय क्षेत्र को देय बैंक ऋण में वृद्धि वर्ष 2018 के दौरान मंद पड़ गयी और इसके बाद वर्ष 2019 के दौरान इसमें बहाली आयी लेकिन असमान रूप

चार्ट II.2: निजी गैर-वित्तीय क्षेत्र को बैंक ऋण



टिप्पणी: संवृद्धि दर की गणना बकाया क्रेडिट से यूएसडालर में की गयी है।

स्रोत: बैंक फॉर इंटरनैशनल सेटिलमेंट्स, कुल क्रेडिट संबंधी आंकड़े।

¹⁷ कुल पूंजी का 2.5 प्रतिशत का बफर रखा जाना है जिसका उद्देश्य बैंकों को न्यूनतम नियामक पूंजी पर्याप्तता अनुपात का उल्लंघन करने से रोकना है।

¹⁸ ये आंकड़े अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) कुल क्रेडिट सांख्यिकी, 14 सितंबर, 2020 तक अद्यतन, जो <https://www.bis.org/statistics/totcredit.htm> पर उपलब्ध हैं।

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2019-20

से (चार्ट II.2)। अमेरिका में, ऋण वृद्धि लगातार बनी रही। दूसरी ओर, वर्ष 2019 के दौरान आस्ट्रेलिया, ग्रीस, इटली, पुर्तगाल, स्पेन और तुर्की में बैंक क्रेडिट में लगातार संकुचन आया।

II.18 देश विशेष से जुड़े कारकों के कारण 2020 में अलग-अलग देशों में बैंक ऋणों में अलग-अलग मात्रा में वृद्धि देखने को

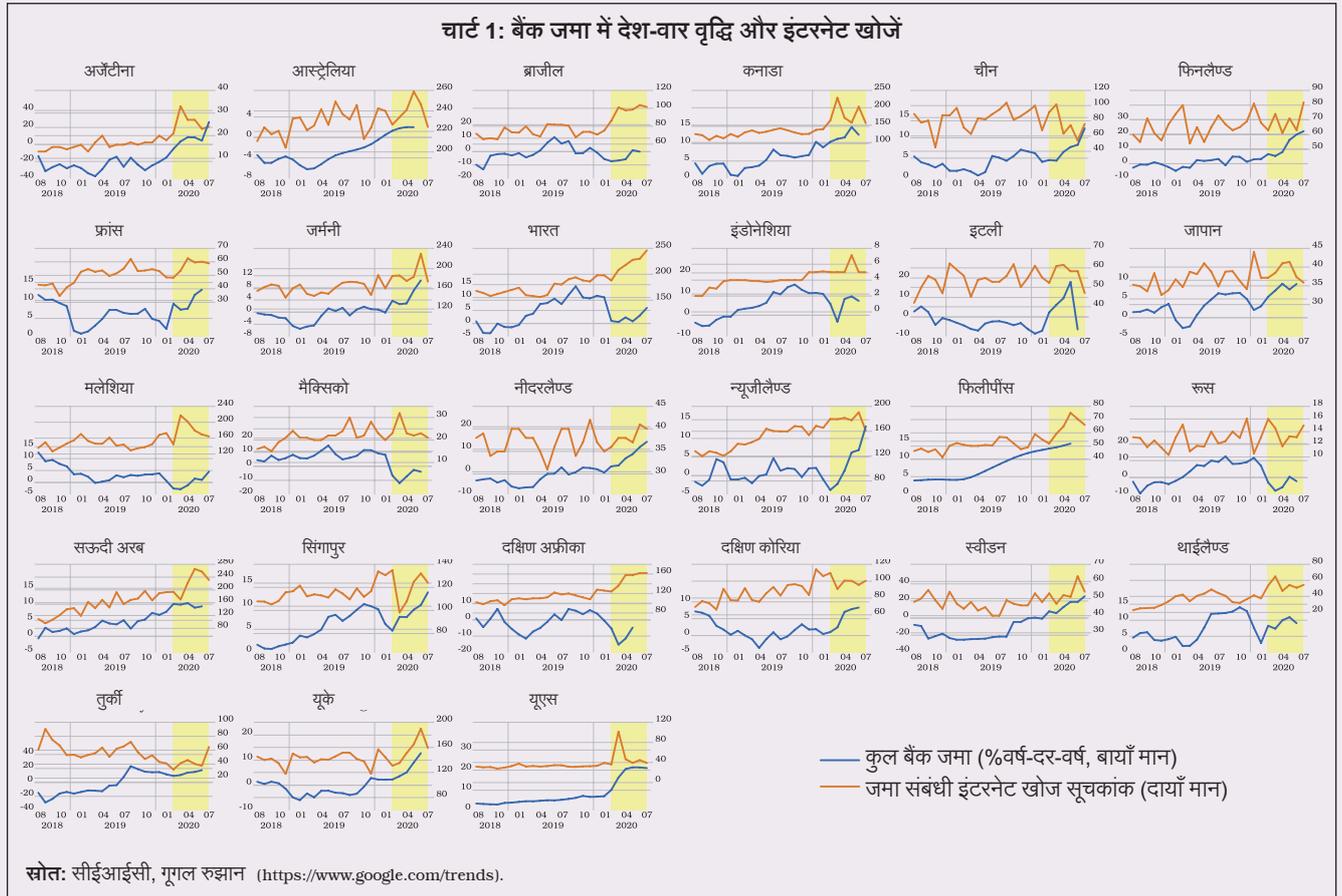
मिली। पहली तिमाही में, कोविड-19 महामारी के कारण सभी एई में बैंक ऋणों में वृद्धि में अचानक गिरावट (हालांकि यूरो क्षेत्र में यह तुलनात्मक रूप से कम) देखी गयी जो कि ईएमडीई में ज्यादा तीव्र रही। दूसरी तिमाही में आंशिक बहाली देखी गयी। हालांकि, बैंक जमा पर कोविड-19 का प्रभाव अलग-अलग देशों में अलग-अलग रहा (बॉक्स II.1)।

बॉक्स II.1: बैंक जमा पर कोविड-19 का प्रभाव अलग-अलग देशों में अलग-अलग क्यों रहा?

उच्च अनिश्चितता की अवधि के दौरान लोगों द्वारा एहतियात बरते जाने के कारण बैंक जमा की आवक में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखती है जो प्रायः प्रकट रूप से बीमा द्वारा तथा अप्रकट रूप से सरकारी गारंटी द्वारा प्रेरित होता है (गटेव और स्ट्रान, 2006; पेनाकची, 2006)। ज्यादातर देशों में बैंक जमा के लिए

इंटरनेट सर्च इंडेक्स¹⁹ महामारी के प्रकोप के बाद तेजी से बढ़ा। जमाकर्ता अपनी जमा राशि की स्थिति और सुरक्षा के बारे में अधिक जानकारी माँगने लगे, और अपने पैसे जमा करने के लिए तुलनात्मक रूप से उच्च ब्याज दरों की ओर आकर्षित हुए (चार्ट 1)।

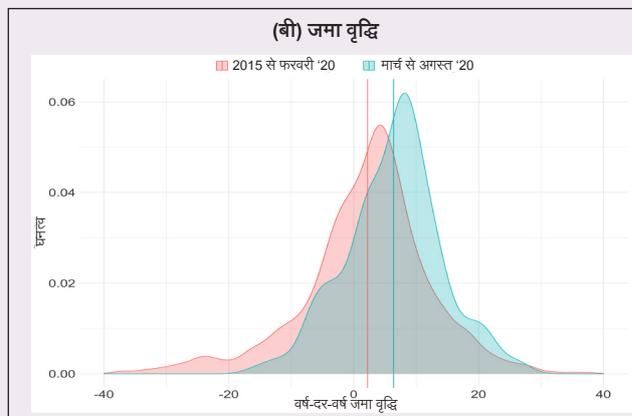
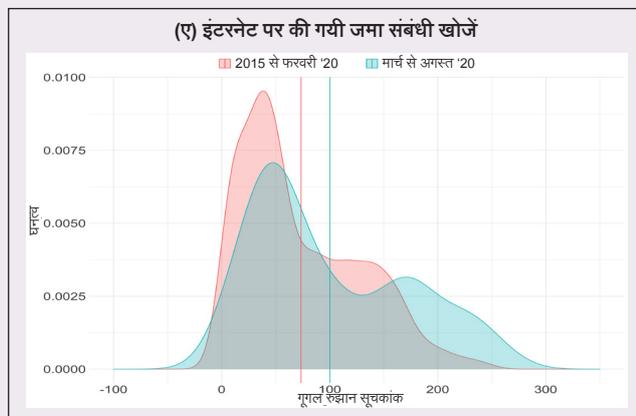
चार्ट 1: बैंक जमा में देश-वार वृद्धि और इंटरनेट खोजें



(जारी...)

¹⁹ कैस्टेलनोवो और ट्रान (2017) की कार्यप्रणाली के अनुसार, गूगल ट्रेंड्स से प्राप्त कच्चे आंकड़ों का प्रयोग करते हुए 'डिपॉजिट' शब्द पर आधारित प्रमुख शब्दों- 'बैंक डिपॉजिट', 'डिपॉजिट', 'बैंक अकाउंट' और 'डिपॉजिट इश्योरेंस' - के लिए सूचकांक तैयार किए गए थे। उन देशों के लिए जहाँ अंग्रेजी आधिकारिक तौर पर बोली जाने वाली भाषा नहीं है, इन खोजों के पूरक के तौर पर मातृ भाषा में अनुवाद भी दिया जाता था।

चार्ट 2: पूर्ण नमूना बैंक जमा और इंटरनेट पर की गयी खोजें: कोविड-पूर्व और पश्चात



स्रोत: सीईआईसी, गूगल रुझान, लेखकों की गणना

पूरे प्रतिदर्श को देखें तो, इंटरनेट पर जमा से संबंधित खोजों में आया उछाल बैंक जमा में हुई वृद्धि के आंकड़ों से मेल खाता है, यदि महामारी से पहले की स्थिति से तुलना की जाए तो (चार्ट 2)। हालांकि, अलग-अलग देशों में बैंक जमा में वृद्धि को देखें तो यह पता चलता है कि इसमें तेजी और मंदी के लगभग बराबर चक्र आए।

औसतन, महामारी के दौरान जिन देशों में इंटरनेट खोजें माध्य²⁰ से अधिक रहीं, उनमें आंकड़ों के लिहाज से बैंक जमा में वृद्धि भी उल्लेखनीय रही (चार्ट 3 ए और सारणी 1)। एई में बैंक जमा राशियाँ ईएमई की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ीं (चार्ट 3 बी)।

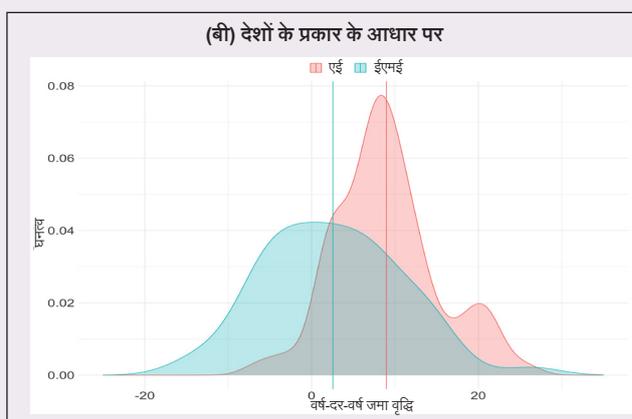
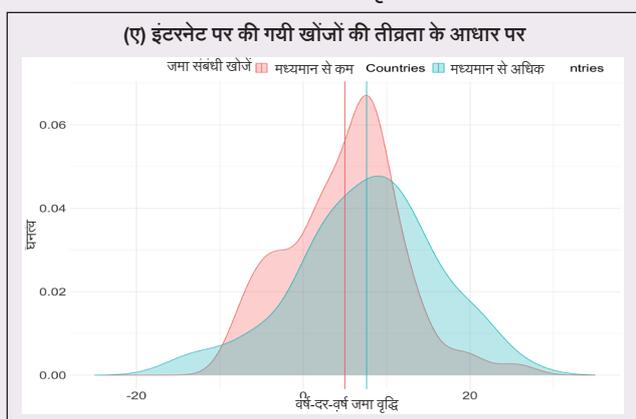
जहाँ नकदी की मात्रा के आधार पर जमा-वृद्धि में अलग-अलग देशों के बीच कोई उल्लेखनीय अंतर नहीं पाया जाता, वहीं ऐसे देशों में जहाँ की बैंकिंग प्रणाली में पूंजी की स्थिति बेहतर है, वहाँ अपने समतुल्य देशों की तुलना में

जमा वृद्धि दर अधिक रही (चार्ट 4 ए और बी)।

उन देशों में जिन्होंने कठोर नीतिगत कदम उठाए, उनकी तुलना में ऐसे देशों में जिनमें उदार नीतियाँ अपनायीं गयीं, जमा वृद्धि में आंकड़ों की दृष्टि से कोई अंतर नहीं देखा गया (चार्ट 5 ए)। हालांकि, यह दिलचस्प है कि, जिन देशों ने कोविड-19 की प्रतिक्रियास्वरूप अधिक आर्थिक सहायता पैकेज प्रदान किए, उनमें आंकड़ों की दृष्टि से बैंक जमा राशियों में उच्चतर वृद्धि-दर देखी गयी (चार्ट 5 बी)।

सारांश रूप में, इन निष्कर्षों से यह पता चलता है कि बेहतर सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था वाली अर्थव्यवस्थाएं एहतियाती उद्देश्यों के लिए बचत करने में अपने नागरिकों की सहायता कर सकती हैं। यह इस प्रकार की महामारी जैसी अकल्पनीय घटनाओं को देखते हुए एक अधिक मजबूत और पूंजी-पर्याप्तता वाली बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

चार्ट 3: जमा वृद्धि दर: इंटरनेट पर की गयी खोजों और विभिन्न प्रकार के देशों के आधार पर



स्रोत: सीईआईसी, गूगल रुझान, लेखकों की गणना

(जारी...)

²⁰ उक्त नमूने में सभी देशों के लिए मीडियन की गणना की गयी।

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2019-20

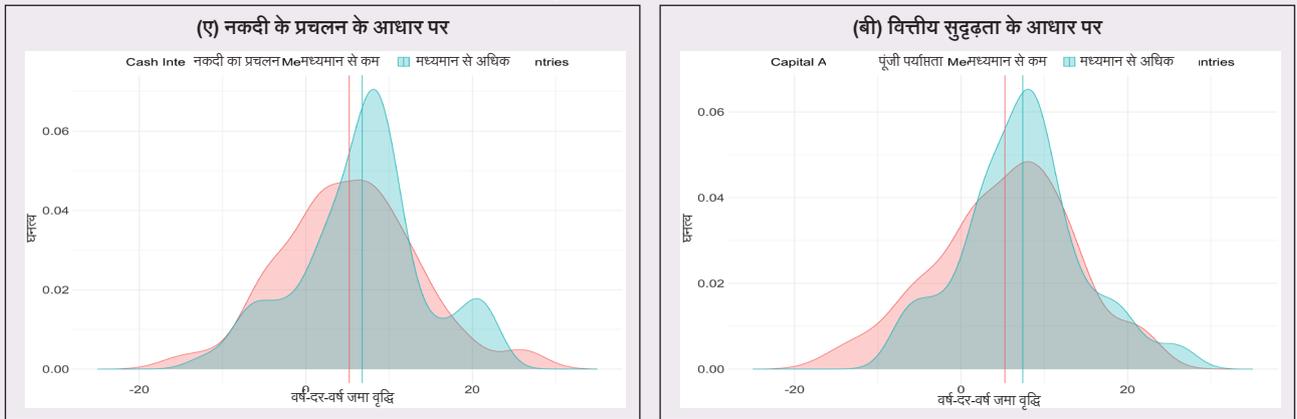
सारणी 1: माध्य में अंतर के लिए सांख्यिकीय परीक्षण

	जमा वृद्धि का माध्य (मानक त्रुटि)	टी-स्टैट	पी-मूल्य
1. इंटरनेट खोज	कम 5.0 (0.81) अधिक 7.6 (1.03)	-1.99	0.04
2. देशों के प्रकार	ईई 9.0 (0.69) ईएमई 2.5 (1.08)	4.96	0.00
3. नकदी का प्रचलन	कम 5.2 (1.04) अधिक 6.8 (0.94)	-1.12	0.27
4. वित्तीय सुदृढ़ता	कम 5.3 (0.99) अधिक 7.4 (0.86)	-1.74	0.08
5. मौद्रिक सख्ती	कम 7.2 (0.89) अधिक 5.4 (0.96)	1.36	0.18
6. आर्थिक सहायता	कम 4.7 (1.14) अधिक 9.1 (0.88)	-3.04	0.00

नोट: कम या अधिक श्रेणियों का निर्धारण विभिन्न वर्गों की माध्यिका के आधार पर किया गया है।

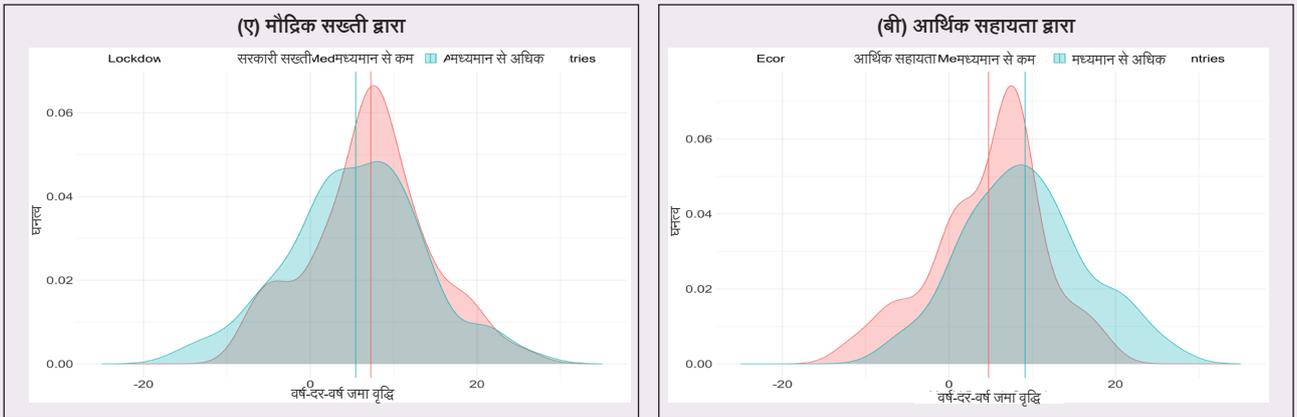
स्रोत: सीईआईसी, बीआईएस, गूगल रुझान, लेखकों की गणना

चार्ट 4: जमा वृद्धि दर: देशों के प्रकार के आधार पर



स्रोत: सीईआईसी, बीआईएस, आईएमएफ, लेखकों की गणना

चार्ट 5: जमा वृद्धि दर: वैश्विक महामारी पर नीतिगत प्रतिसाद



स्रोत: सीईआईसी, ऑक्सफोर्ड पॉलिसी ट्रेकर, लेखकों की गणना

संदर्भ

कैस्टेलुनोवो, ई., और ट्रान, टी. डी. (2017): 'गूगल इट अप! अ गूगल ट्रेड्स बेस्ड अनसर्टेनटी इंडेक्स फॉर दि यूनाइटेड स्टेट्स एण्ड ऑस्ट्रेलिया', इकोनॉमिक्स लेटर्स, 161, 149-15.

गटेव, ई., और पी. ई. स्ट्रुहान (2006): 'बैंक्स एडवांटेज इन हेजिंग लिक्विडिटी रिस्क: थियरी एंड एविडेंस फ्रॉम दि कॉमर्सियल पेपर मार्केट', जर्नल ऑफ फाइनेंस, 61, 867-892.

हेरवाडकर, एस, प्रताप, बी., चक्रवर्ती, एच. (2020): 'रेस्पॉन्स ऑफ बैंक डिपॉजिट्स टु कोविड-19: अ क्रॉस-कंट्री एनालिसिस', मिमियो.

पेनाकची, जी. (2006): 'डिपॉजिट इश्योरेंस, बैंक रेगुलेशन, एण्ड फाइनेंशियल सिस्टम रिस्क', जर्नल ऑफ मॉनेटरी इकोनॉमिक्स 53, 1-30.

3.2 आस्ति गुणवत्ता²¹

II.19 वर्ष 2019 के दौरान सभी प्रमुख एई में आस्ति गुणवत्ता में आम तौर पर सुधार हुआ (चार्ट II.3ए)²²। गौरतलब है कि, यूरो क्षेत्र की दो गौण अर्थव्यवस्थाओं, यथा, ग्रीस और पुर्तगाल में मुख्य रूप से संस्थागत और सरकारी हस्तक्षेपों के बल पर अनर्जक आस्तियों का अनुपात घटा महामारी के माहौल में वर्ष 2020 की प्रथम छमाही में आस्ट्रेलिया, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में आस्ति गुणवत्ता में गिरावट आयी।

II.20 ईएमई में बैंकिंग प्रणाली की आस्ति गुणवत्ता की तस्वीर मिली-जुली रही (चार्ट II.3बी)। उदाहरण के लिए, रूसी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता नाजुक आर्थिक परिस्थितियों और प्रतिबंधों के कारण 2018 और 2019 की शुरुआत में खराब रही, लेकिन बाद में इसमें सुधार हुआ है। हालांकि, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की के वित्तीय हालात बिगड़ जाने के कारण उनके बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट आयी। वर्ष 2020 की प्रथम छमाही में ब्राजील, भारत और तुर्की की आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ।

II.21 भविष्य की बात करें तो, अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि बैंकों की आस्ति गुणवत्ता पर महामारी का कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इन देशों में ठहराव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। जहाँ बैंकों को अपने संचित पूंजी बफ़र से इस महामारी से जुड़ी कठिनाइयों का सामना करने में मदद मिल सकती है, वहीं यह महत्वपूर्ण है कि बैंकों की बैलेंस शीट पर मौजूद दबाव को साफ-साफ देखा जा सकता है।

3.3 आस्तियों पर प्रतिलाभ

II.22 वर्ष 2019 के दौरान सभी एई और ईएमई में बैंकों की लाभप्रदता, जिसे आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) से मापा जाता है, आम तौर पर घटी। कम लाभप्रदता वाले समग्र वातावरण में, कनाडा, आस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम के बैंकों ने अमेरिका और जापान के बैंकों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया (चार्ट II.4ए)। यूरो क्षेत्र की

बात करें तो, फ्रांस और जर्मनी में बैंक की लाभप्रदता पर कमजोर वृद्धि-दर और अनर्जक ऋणों के उच्च स्तर के कारण विपरीत प्रभाव पड़ा, जबकि ग्रीस, पुर्तगाल और स्पेन जैसी गौण अर्थव्यवस्थाओं में एनपीएल अनुपातों में गिरावट आने और परिणामस्वरूप ऋणों पर होने वाली हानि के लिए कम प्रावधान की आवश्यकता से बैंकों की लाभप्रदता में बहाली आयी। हालांकि, इस पूरे क्षेत्र को देखा जाए तो, कम लागत-दक्षता, आय के सीमित विविधीकरण और कुछ देशों में लंबे समय से चली आ रही अनर्जक आस्तियों के भारी भंडार जैसी संरचनात्मक कमजोरियां इनके बैंकों के बेहतर पुनरुद्धार के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं।

II.23 ईएमई में भी, 2019 में बैंकों की लाभप्रदता पिछले वर्ष की तुलना में कम रही। यद्यपि भारत में बैंकों का आरओए समतुल्य देशों में सबसे कम बना रहा, 2019 में वे हालिया घाटे के दौर से उबरते हुए लाभप्रदता की स्थिति में आ गए थे। इंडोनेशिया में बैंकों ने उच्च ब्याज मार्जिन और तीव्र ऋण वृद्धि के बल पर पूरे दशक के दौरान अपने प्रदर्शन में सुधार जारी रखा और इनके बाद मेक्सिको, ब्राजील और थाईलैंड के बैंकों का स्थान आता है (चार्ट II.4 बी)। आस्ति गुणवत्ता, कर्जपोषित आस्तियों के लगातार बढ़ने, ऋण वृद्धि की दर कम होते जाने और विशेष रूप से छोटे और मँझले आकार के बैंकों के तुलन-पत्रों की स्थिति कमजोर हो जाने से जुड़ी चिंताओं के चलते चीन में बैंकों की लाभप्रदता पर दबाव बना। रूस में ऋण चूक की घटनाएं अधिक होने के बावजूद उनके बैंकों की लाभप्रदता में सुधार हुआ क्योंकि एनपीएल के लिए प्रावधान अच्छी तरह कर लिए गए थे तथा निवल ब्याज आय और शुल्क और कमीशन आय दोनों में वृद्धि हुई।

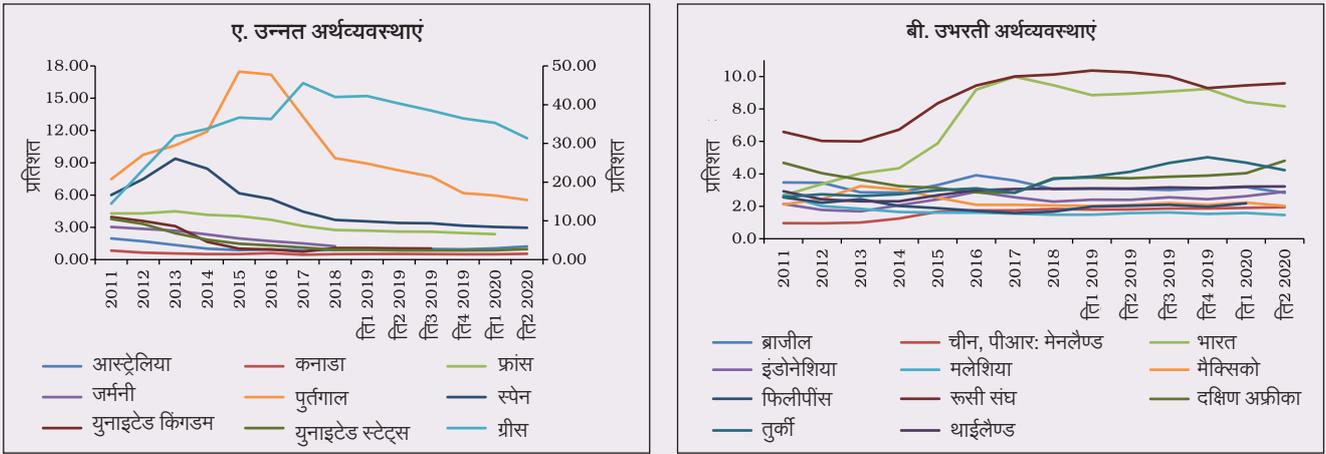
II.24 सभी उन्नत और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में आम तौर पर बैंकों की लाभप्रदता पर वर्ष 2020 की प्रथम छमाही में विपरीत प्रभाव पड़ा। आगे चलकर, ऋण वृद्धि की रफ्तार मंद पड़ने, कम ब्याज दर वाला परिदृश्य बने रहने की संभावना और महामारी के कारण आस्तियों पर निकट भविष्य में आने वाला दबाव इस बात का संकेत करता है कि बैंकों की लाभप्रदता में कमी जारी रहेगी।

²¹ उपखण्ड 4.2 से 4.4 तक के आंकड़े आईएमएफ के वित्तीय सुदृढ़ता सूचकांकों (एफएसआई) से लिए गए हैं।

²² आस्ति की गुणवत्ता कुल सकल ऋणों की तुलना में गैर-निष्पादित ऋणों (एनपीएल) के अनुपात के रूप में मापी जाती है।

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2019-20

चार्ट II.3: अनर्जक ऋणों का अनुपात (प्रतिशत में)



3.4 पूंजी पर्याप्तता

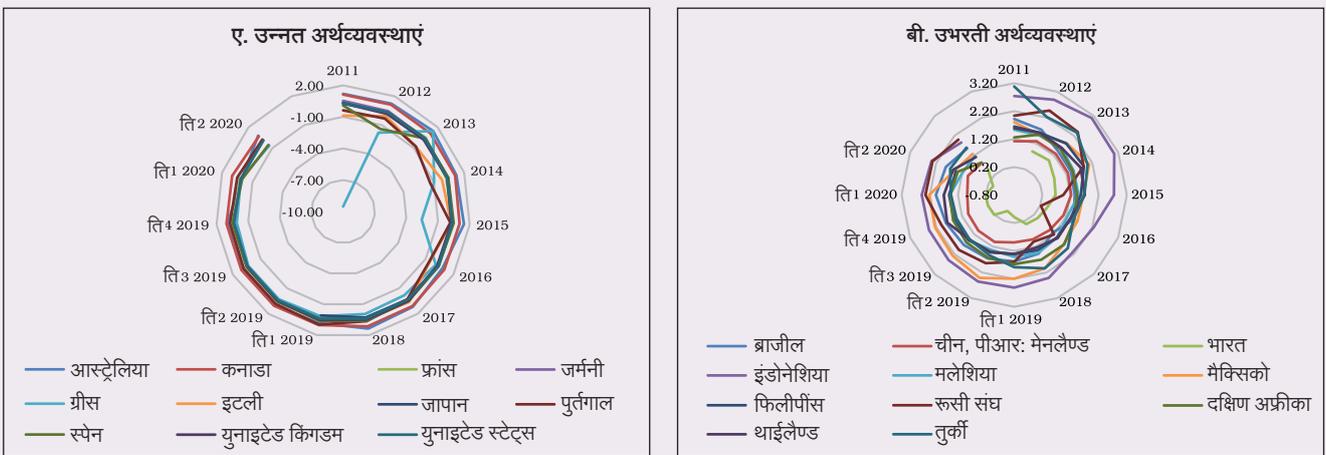
II.25 सभी देशों में बासेल III मानदंडों के कार्यान्वयन में लगातार प्रगति हुई है, हालांकि इसकी गति अलग-अलग अवश्य रही है। एई और ईएमई में सभी प्रणालीगत बैंक पूंजी पर्याप्तता बनी रही (चार्ट II.5ए और बी)।

II.26 ब्राजील को छोड़कर, सभी प्रमुख ईएमई के बैंकों ने 2019 में अपनी पूंजी पर्याप्तता में सुधार किया। इंडोनेशिया के बैंकों ने उच्चतम सीआरएआर बनाए रखा। चीनी बैंकों, विशेष रूप से छोटे और मझले आकार के बैंकों, ने अपनी पूंजी की

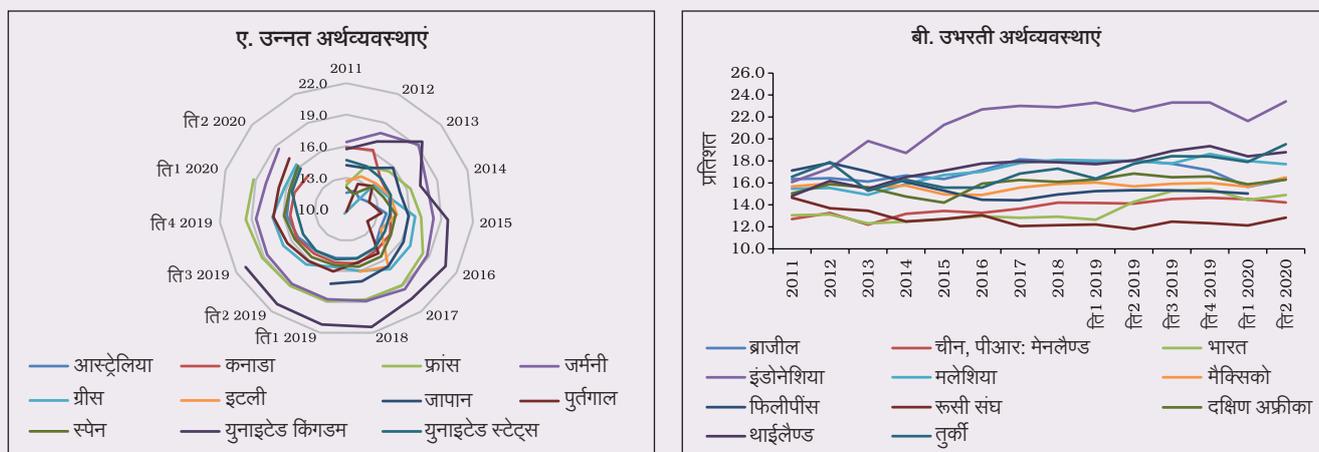
स्थिति को मजबूत किया। रूसी बैंकों की पूंजी पर्याप्तता में 2019 में सुधार हुआ, हालांकि उनका स्थान ईएमई में सबसे नीचे रहा। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार द्वारा पूंजी डाले जाने और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पूंजी जुटाने के लिए किए गए प्रयासों के बल पर बैंकों के सीआरएआर में सुधार हुआ।

II.27 वैश्विक बैंकिंग प्रणाली ने इस महामारी से उत्पन्न संकट की स्थिति से निपटने में सफलता पायी क्योंकि उनकी पूंजी और चलनिधि की स्थिति उस समय की तुलना में बेहतर हो गयी थी

चार्ट II.4: आस्तियों पर प्रतिलाभ (प्रतिशत में)



चार्ट II.5: पूंजी-जोखिम भारित आस्ति अनुपात (प्रतिशत)



स्रोत: वित्तीय सुदृढता सूचकांक, आईएमएफ और पर्यवेक्षी विवरणियाँ, आरबीआई.

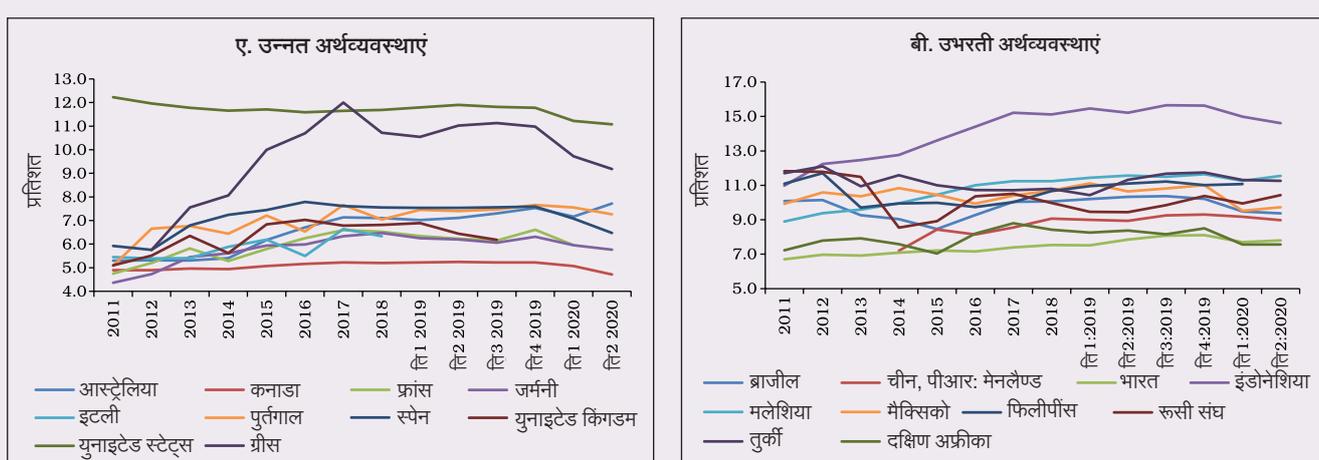
जब वैश्विक वित्तीय संकट की शुरुआत हुई थी। हालांकि, ऐसी आशंका है कि भविष्य में इस महामारी के कारण पूंजी और चलनिधि बफ़र पर दबाव बढ़ेगा।

3.5 कर्ज पोषित आस्ति (लीवरेज) अनुपात²³

II.28 वर्ष 2019 में आई और ईएमई दोनों की बैंकिंग प्रणालियों में कर्ज पोषित आस्तियों के अनुपात में आम तौर पर सुधार हुआ जो कि 2010 के बाद पहली बार देखा गया था

और इसके मूल में बासेल III विनियामकीय अपेक्षाएं थीं। बैंकों ने बासेल III मानदंडों के तहत लीवरेज अनुपात को न्यूनतम 3 प्रतिशत से अधिक बनाए रखा है। जहाँ यूएस और ग्रीस के बैंकों ने अपना लीवरेज अनुपात 11 प्रतिशत से ऊपर बनाए रखा है, वहीं इंडोनेशिया के बैंकों का लीवरेज अनुपात पिछले तीन वर्षों में लगातार 15 प्रतिशत से ऊपर बना हुआ है (चार्ट II.6ए और बी)।

चार्ट II.6: कर्ज-पोषित आस्ति (लीवरेज) अनुपात (प्रतिशत)



स्रोत: वित्तीय सुदृढता सूचकांक, आईएमएफ.

²³ कुल आस्ति की तुलना में पूंजी के अनुपात के रूप में मापा जाता है।

3.6 वित्तीय बाजार संकेतक

II.29 कम लाभप्रदता वाले माहौल में बैंक ऋणों में वृद्धि की सुस्त पड़ती रफ्तार के बावजूद वर्ष 2019 में बैंक स्टॉक सूचकांकों में आम तौर पर उछाल दर्ज किया गया जो आस्ति गुणवत्ता और पूंजी पर्याप्तता में सुधार का परिचायक है। मार्च में जैसे ही महामारी की मार पड़ी, ये सूचकांक नीचे लुढ़क गए लेकिन अब इनमें बहाली आ गयी है हालांकि इनका स्तर कोविड-पूर्व के स्तर से अभी भी नीचे बना हुआ है (चार्ट II.7ए)।

II.30 बैंकों के क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (सीडीएस) के स्प्रेड्स, जो 2018 की दूसरी छमाही से बढ़ना शुरू हो गए थे, वे 2019 की शुरुआत के आसपास चरम पर पहुंच गए और मार्च 2020 तक उनमें गिरावट आनी प्रारंभ हुई जब महामारी का प्रकोप फैला। यूके, उत्तरी अमेरिका और चीन में बैंकों का सीडीएस स्प्रेड निम्न स्तर पर रहा और उनमें अत्यंत नजदीकी वाला उतार चढ़ाव देखा गया²⁴। यूरोपीय बैंकों का सीडीएस स्प्रेड थोड़ा अधिक रहा, संभवतः सरकारी क्रेडिट की रेटिंग अपेक्षाकृत कम रहने, ऋणों की खराब गुणवत्ता और गौण अर्थव्यवस्थाओं में

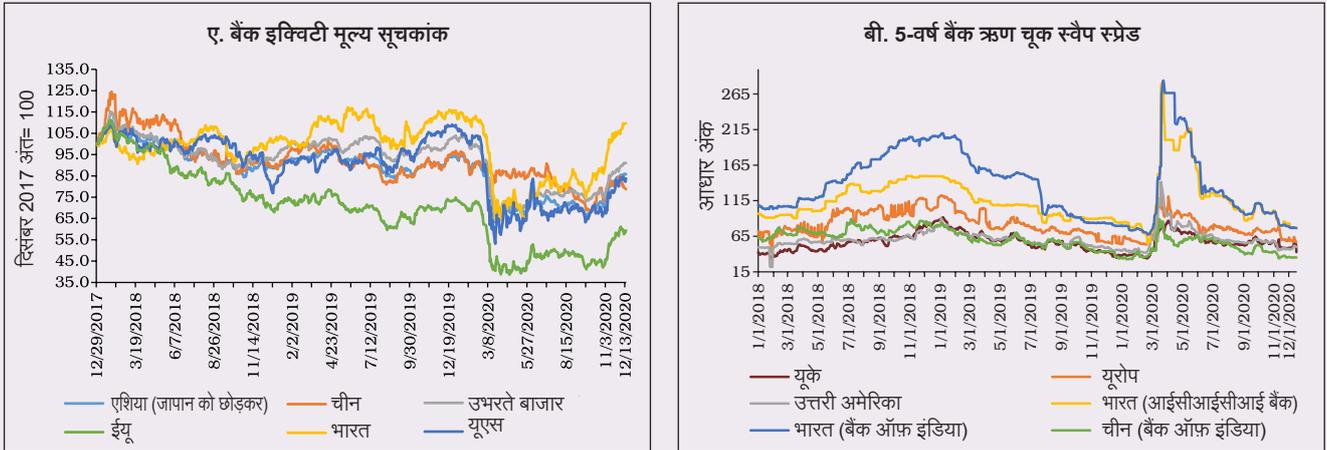
मौजूद राजनीतिक अनिश्चितताएं इसके मूल में थीं। महामारी के कुप्रभाव के मद्देनजर सीडीएस स्प्रेड में मार्च 2020 में फिर से तीव्र उछाल आया लेकिन इसी महीने के अंत तक इसमें फिर से तेज गिरावट देखी गयी जो समय पर उठाए गए अभूतपूर्व नीतिगत कदमों को दर्शाता है (चार्ट II.7बी)।

4. दुनिया के सबसे बड़े बैंक²⁵

II.31 टियर-1 पूंजी के आधार पर किए गए श्रेणीनिर्धारण के अनुसार दुनिया के शीर्ष 100 बैंकों के तुलन-पत्रों में वर्ष 2019 में कुल संपत्ति के मामले में वृद्धि देखी गयी और भिन्न-भिन्न बैंकों के बीच काफी अंतर दिखायी दिया। इसके अलावा, वर्ष 2019 के दौरान इन बैंकों के कर-पूर्व लाभों में भी पर्याप्त अंतर रहा। बैंकों की संख्या और परिसंपत्तियों के कुल मूल्य (अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में) की दृष्टि से आई और ईएमई दोनों ने 2019 में शीर्ष 100 बैंकों में अपनी स्थिति को बरकरार रखा (चार्ट II.8ए और बी)।

II.32 वर्ष 2019 में शीर्ष 100 बैंकों में परिसंपत्ति की गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ, और 75 प्रतिशत बैंकों में एनपीएल

चार्ट II.7: बैंकों की मजबूती के बाजार-आधारित संकेतक

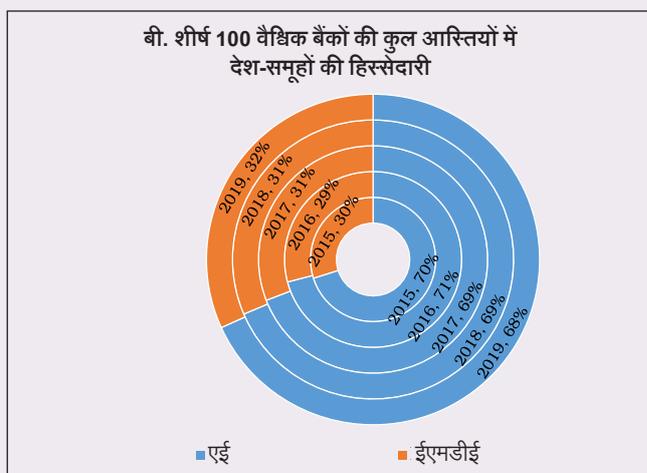
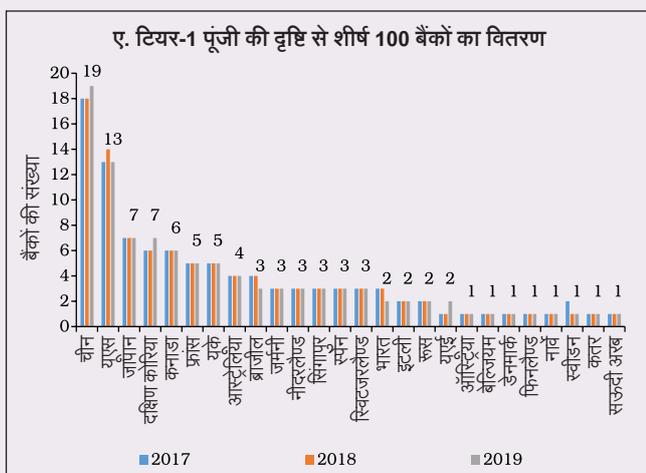


स्रोत: डेटास्ट्रीम

²⁴ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (सीडीएस) स्प्रेड बैंकों की कथित शोधन क्षमता और उनकी पुनर्वित्तीयन क्षमता को दर्शाता है। कम और अधिक स्थिर सीडीएस स्प्रेड वाले बैंक कम जोखिम प्रीमियर का भुगतान करते हैं जिसके कारण वे अपने ग्राहकों को अपेक्षाकृत सस्ता और आसान शर्तों पर वित्तपोषण उपलब्ध करा पाते हैं।

²⁵ ये आंकड़े फाइनेंशियल टाइम्स के बैंकर डेटाबेस से लिए गए हैं।

चार्ट II.8: टियर-1 पूंजी की दृष्टि से शीर्ष 100 बैंकों का वितरण



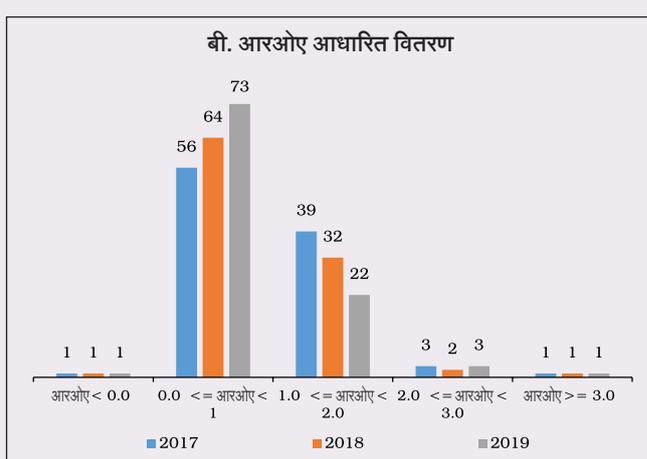
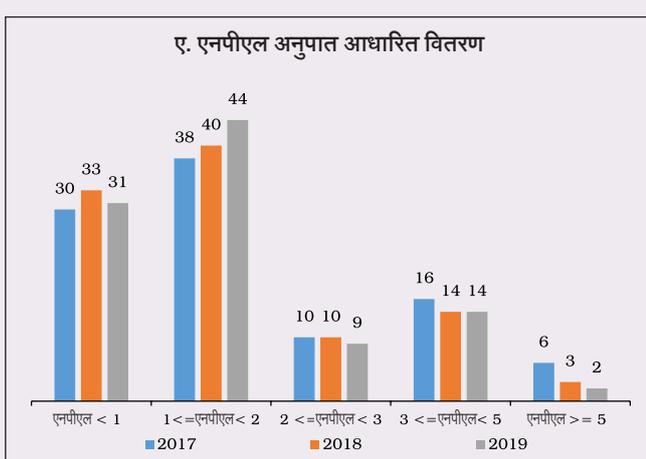
स्रोत: दि बैंकर डेटाबेस, फाइनेंशियल टाइम्स।

अनुपात 2 प्रतिशत से कम रहा। हालांकि, शीर्ष 100 बैंकों के माध्य आरओए में 2019 में लगातार दूसरे वर्ष गिरावट आयी (चार्ट II.9ए और बी)।

II.33 इन शीर्ष 100 बैंकों में पूंजी की स्थिति मजबूत रही और इनमें से आधे से अधिक ने वर्ष 2019 में 16 प्रतिशत से अधिक सीआरएआर दर्ज किया गया। इसी प्रकार, लीवरेज

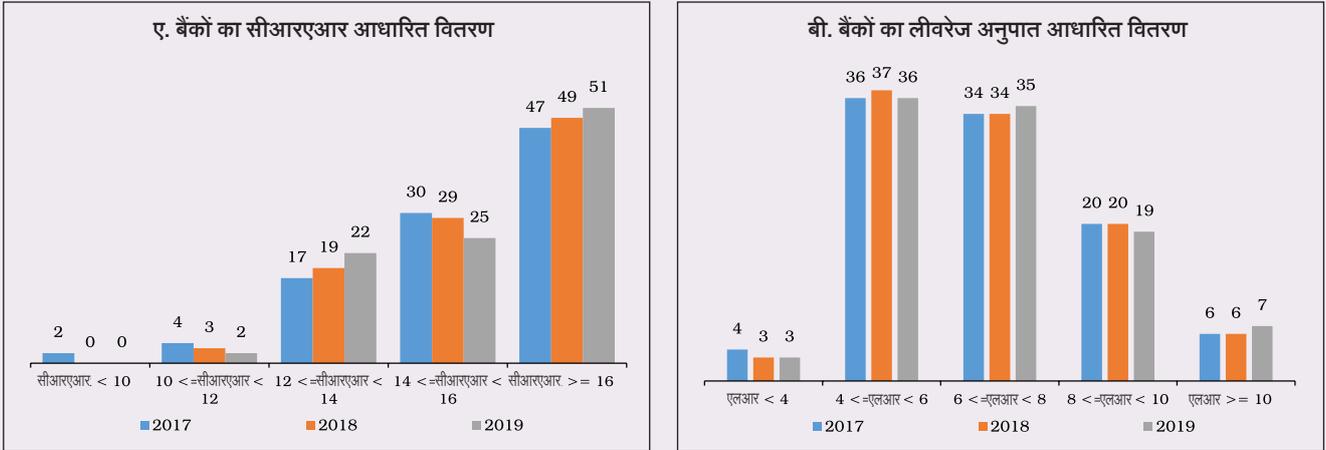
अनुपात (पूंजी-आस्ति अनुपात) में मामूली सुधार हुआ और 70 प्रतिशत से थोड़ा अधिक बैंकों का लीवरेज अनुपात 4 से 8 प्रतिशत की सीमा में रहा। तीन बैंकों, फ्रांस, जर्मनी और जापान प्रत्येक देश में एक-एक बैंक, लीवरेज अनुपात 4 प्रतिशत से थोड़ा नीचे, परंतु बासेल III विनियमों में प्रस्तावित 3 प्रतिशत से ऊपर रहा (चार्ट II.10ए और बी)।

चार्ट II.9: शीर्ष 100 बैंकों की आस्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता



टिप्पणी: कुछ आंकड़े उपलब्ध न हो सकने के कारण यह संभव है कि बैंकों की संख्या का योग 100 न हो।
स्रोत: दि बैंकर डेटाबेस, फाइनेंशियल टाइम्स।

चार्ट II.10: शीर्ष 100 बैंकों की बैंक सुदृढ़ता



टिप्पणी: कुछ आंकड़े उपलब्ध न हो सकने के कारण यह संभव है कि बैंकों की संख्या का योग 100 न हो।
 स्रोत: दि बैंकर डेटाबेस, फाइनेंशियल टाइम्स।

5. निष्कर्ष

II.34 वर्ष 2019 में वैश्विक संवृद्धि और ऋण वृद्धि में गिरावट आने के साथ ही, परिसंपत्ति की गुणवत्ता में सुधार और अपेक्षाकृत अधिक पूंजी और चलनिधि की मौजूदगी के बावजूद, बैंक लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लगाए गए प्रतिबंध और लॉकडाउन किसी बहुत बड़े आर्थिक आघात सदृश थे जिनकी वजह से हाल में आर्थिक मंदी पैदा हो गयी थी। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद प्रारंभ किए

गए वैश्विक वित्तीय क्षेत्र के सुधारों का कार्यान्वयन पुनः प्रारंभ होने पर वैश्विक स्तर पर बैंकिंग प्रणाली में मजबूती आएगी। प्राधिकारियों ने महामारी से उत्पन्न सदमे को नियंत्रित करने के लिए तेजी से और निर्णायक रूप से कार्य किया है। हालांकि, 2021 का वैश्विक वित्तीय प्रणाली परिदृश्य अनिश्चित बना हुआ है, कुछ देशों में आर्थिक गतिविधियों की गति में आशातीत बहाली से यह उम्मीद जगी है कि ये 2021 में अपनी सामान्य स्थिति में लौट आएंगी।